



## 36वाँ मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी वसित्त वश्लेषण प्रशक्षण कार्यक्रम

नेशनल ई-गवर्नेस डव्जिन (NeGD) ने अपनी कषमताओं में बढोतरी के उद्देश्य से एक वश्लेषण परयोजना के तहत 36वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (Chief Information Security Officers- CISO) वसित्त वश्लेषण प्रशक्षण कार्यक्रम का आयोजन कया। नई दलिली के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजत इस अभ्यास सत्र में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों एवं केंद्रशासतल प्रदेशों के 24 प्रतभागयों ने भाग लया।

- यह प्रशक्षण कार्यक्रम [साइबर सुरक्षतल भारत पहल](#) के तहत आयोजतल कार्यशालाओं की शृंखला का एक हसलसा है।

### साइबर सुरक्षतल भारत पहल:

- साइबर सुरक्षतल भारत पहल की संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी वभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारयों (CISOs) एवं अग्रमल पंकतल के सूचना प्रौद्योगकल अधिकारयों की कषमता नरमाण के मशिन के साथ की गई थी।
- इसे इलेक्ट्रॉनकलस और सूचना प्रौद्योगकल मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) द्वारा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेस डव्जिन (NeGD) तथा भारत में वभलनल उद्योग भागीदारों के सहयोग से लॉन्च कया गया था।

### मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी वसित्त वश्लेषण प्रशक्षण कार्यक्रम:

- परचय:
  - यह प्रशक्षण [सार्वजनकल नजल भागीदारल](#) (Public Private Partnership- PPP) मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघों के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारल है।
- उद्देश्य:
  - साइबर खतरों के उभरते परदृश्य को लेकर जागरूकता उत्पन्न करना।
  - साइबर संबंधतल समाधानों की गहन समझ प्रदान करना।
  - साइबर सुरक्षा से संबंधतल रूपरेखा, दशल-नरदेश और नीतयों का नरमाण करना।
  - सफलता और असफलताओं से सीखने के लयल सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करना।
  - साइबर सुरक्षा से संबंधतल मुद्दों पर उनके संबंधतल कार्यात्मक कषेत्र में सूचतल नरणय लेने के लयल महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना।
- प्रतभागल:
  - यह कार्यक्रम मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारयों (CISO) और वभलनल मंत्रालयों एवं वभागों के अग्रमल पंकतल के IT अधिकारयों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनकल उपकरमों और बैंकों सहतल अन्य के लयल आयोजतल कया जाता है।
- प्रशक्षण:
  - नेशनल ई-गवर्नेस डव्जिन (NeGD) प्रशक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु रसद सहायता प्रदान करता है, जबकल उद्योग संघ प्रशक्षण के लयल तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
  - उद्योग के प्रशक्षण भागीदार माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, पालो अलटो नेटवर्क्स, E&Y और डेल-EMC, [NIC](#), [CERT-In](#) तथा [CDAC](#) सरकार की ओर से भागीदार हैं।

### साइबर सुरक्षा बढाने से संबंधतल अन्य पहलें:

- वैश्वकल:
  - [साइबर क्राइम पर बुडापेसट अभसमय](#)
  - [इंटरनेट गवर्नेस फोरम \(IGF\)](#)
- भारत-वशलषलतल:
  - [राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीतल 2020](#)
  - [राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरकषण केंद्र \(NCIIPC\)](#)
  - [भारतीय साइबर अपराध समनवय केंद्र \(I4C\)](#)
  - [साइबर अपराधों का सामना करने के लयल नई सुवधल](#)
  - [कंप्युटर आपातकालीन प्रतकलरयल दल- भारत \(CERT-In\)](#)
  - [डजलतल वयकतगत डेटा संरकषण वधलयक, 2022](#)

- [रक्षा साइबर एजेंसी \(DCyA\)](#)
- [डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023](#)
- [साइबर स्वच्छता केंद्र](#): यह प्लेटफॉर्म वर्ष 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर और वायरस को हटाकर अपने कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साफ करने में मदद करने के लिये पेश किया गया था।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. 'वानाकराई, पेट्या और इंटरनलब्लू' जो पद हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, नमिनलखिति में से कसिसे संबंधित हैं? (2018)

- (a) एक्सोप्लैनेट
- (b) परछन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेंसी)
- (c) साइबर आक्रमण
- (d) लघु उपग्रह

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- रैनसमवेयर दुरभावनापूरण सॉफ्टवेयर (या मैलवेयर) का एक रूप है। एक बार जब यह कंप्यूटर में प्रवेश कर लेता है, तो आमतौर पर डेटा तक पहुँचकर उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुँचाता है। भुगतान करने पर डेटा तक पहुँच बहाल करने का वादा करते हुए हमलावर पीड़ित से फरौती की मांग करता है।
- 'वानाकराई, पेट्या और इंटरनलब्लू' कुछ रैनसमवेयर हैं, जिन्होंने बटिकॉइन (क्रिप्टोकरेंसी) में फरौती के भुगतान की मांग की थी।
- क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसमें मुद्रा की इकाइयों के सृजन को वनियमिति करने और केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से संचालित धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने हेतु एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- अतः विकल्प (c) सही है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/36th-ciso-deep-dive-training-programme>